

फैसला

हाई कोर्ट ने कहा- फंसाने की थी साजिश, घूस की मांग साबित नहीं हुई

रिश्वत केस में मंडल संयोजक कोर्ट से बरी

मिली राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, विलासपुरः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी राहत देते हुए आरोपित मंडल संयोजक को बरी कर दिया है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल रिश्वत की राशि की बरामदगी पर्याप्त नहीं है, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि आरोपित ने स्वेच्छा से पैसे को घूस के रूप में स्वीकार किया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने सुनाया। मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) रायपुर ने 2017 में आरोपित को दो साल की सजा सुनाई थी।



कोर्ट ने की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से सिद्ध हो। केवल पैसे की बरामदगी से अपराध सिद्ध नहीं होता। कोर्ट ने बी. जयराज बनाम ऑंड्राप्रदेश राज्य और नीरज दत्ता बनाम दिल्ली सरकार सहित

यह था पूरा मामला। शिकायतकर्ता वैजनाथ नेताम, उस समय शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक कर्मी और आदिवासी हास्टल के अधीक्षक थे। आरोप लगाया था कि मंडल संयोजक लवन सिंह चुरेन्द्र ने जनवरी 2013 के छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी थी। बाद में वैजनाथने एसीबी में शिकायत दर्ज की।

हाई कोर्ट में क्या हुआ
कोर्ट ने कहा कि, शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता संदिग्ध है। वह पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था। जिस छात्रवृत्ति की मंजूरी को लेकर रिश्वत मांगे जाने का आरोप है, वह पहले ही मंजूर हो चुकी थी और राशि भी निकाल ली गई थी। आरोपित स्वयं शिकायतकर्ता के खिलाफ 50,700 की छात्रवृत्ति गबन की जांच कर रहा था, जिस पर वसूली के निर्देश भी दिए गए थे। इस कारण शिकायतकर्ता की शिकायत को बदले की भावना से प्रेरित माना गया। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई आडियो रिकार्डिंग की सत्यता पर भी सवाल उठे। न तो आवाज की पुष्टि कराई गई, न ही फारेंसिक जांच कराई गई। ट्रैप पार्टी में मौजूद मुख्य गवाहों की गवाही विरोधाभासी पाई गई।